एमएमपी का दो दिवसीय सेमिनार में अध्यक्ष श्रीधर ने कहा

विकास की बने ऐसी नीति, जिसमें खनन पर कम हो निर्भरता

संवाददाता, दुमका

कहा, माओवादी या विकास विरोधी कहकर हमारी बातों को नकारा नहीं जा सकता

कार्यक्रम को संबोधित करते पश्चिम बंगाल से पहुंचे प्रतिनिधि स्वराज, मंचासीन श्रीधर व मौजूद लोग. ■ फोटो । प्रभात खबर

औद्योगिकीकरण एवं विकास के नाम पर कम से कम लोग विस्थापित हों और देश में खनन पर निर्भरता भी कम से कम रहे, ऐसी व्यवस्था किये जाने की जरुरत है.आज जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है, उसके दोहन के लिए जिस रफ्तार से सर्वे किये जा रहे हैं, खदानों की लीज दी जा रही है, उससे लगता है कि औद्योगिक कंपनियां ही नहीं सरकार भी कोयले व खनिज के उपर जमीन में दिखने-मिलने वाली चीजों को बोझ मान रही है. जमीन में क्या है, कितनी वनस्पतियां हैं, उसके जैविक महत्व क्या हैं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है. उक्त बातें भूगर्भ वैज्ञानिक सह मिनरल, माइंस एंड पीपुल (एमएमपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर ने कही. एमएमपी के तत्वावधान में गुरुवार से शुरु हुए दो दिवसीय 'तृतीय नेशनल कोल एंड थर्मल प्लांट गैदरिंग' में श्रीधर ने कहाः हमारा मानना है कि खनिज संपदा के लिए सर्वे अंत में होना चाहिए, भूमि व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बिना जिसका लाभ हम विकास में कर सकते हैं, उसके दोहन के लिए सर्वे पहले होनी चाहिए. सरकार को खेती-बाड़ी, फल-फूल उत्पादन, स्वरोजगार एवं कास्तकार को बढ़ावा देने की पहल करनी चाहिए. उर्जा के लिए वैकल्पिक स्रोतों के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा , बायो गैस आदि को बढ़ावा देना चाहिए. जापान व यूरोप जैसे देश आज न्यक्लियर एनर्जी को बंद कर रहे हैं, हम उसे अपनाने की बात कर रहे हैं. अन्य कई देश तो आज थर्मल पावर भी बंद कर रहे हैं. आज देश में अगर सोलर आधारित मॉडल अपनाया जाय, तो 80 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है, लेकिन इसकी पहल नहीं हो रही है. श्रीधर ने कहाः हम अमेरिका जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार कर आगे नहीं बढ़ सकते. हमें नयी पॉलिसी बनाने की जरूरत है. हम विकास चाहते हैं, लेकिन अलग प्रक्रिया से. श्रीधर ने कहा कि माओवादी या विकास विरोधी कहकर हमारी बातों को नकारा नहीं जा सकता.

मेक इन इंडिया पर भी उठाया सवाल

श्रीधर ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठायां. कहा कि इसके जरिये चार लाख करोड़ रुपये का निवेश देश के अंदर कराने की योजना पर सरकार काम कर रही है. कहा कि अगर मेक इन इंडिया के जरिये 22 लाख लोगों को नौकरी दिला भी दी गयी, तो भी यह सही नहीं होगा, क्योंकि इससे कम से कम एक करोड़ लोगों की खेती-बारी चौपट हो जायेगी.

डीवीसी ही नहीं एचइसी मामले की भी हो जांच

सामाजिक कार्यकर्ता बासवी किड़ो ने कहा कि राज्य में डीवीसी में विस्थापितों के साथ धोखा हुआ है. सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए. उन्होंने एचइसी के भी अतिरिक्त जमीन कथित तौर पर बेचे जाने मामले की भी गहराई से जांच कराने की मांग को रखा. कहा कि 9200 एकड़ जमीन एचइसी के लिए अधिग्रहित किया गया था. 2000 एकड़ जमीन सरप्लस थी, जिसे बेचा जा रहा है. यह जमीन विस्थापितों को वापस दिलायी जानी चाहिए.

नौ राज्यों से जुटे हैं विस्थापन आंदोलनकारी व चिंतक

सोशल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला में 9 राज्यों से तकरीबन 140 विस्थापन आंदोलनकारी व चिंतक भाग ले रहे हैं. एक प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका से भी पहुंची हैं. प्रतिभागियों में हरियाणा के गुमान सिंह, पश्चिम बंगाल के स्वराज, तेलंगाना के केवी प्रताप, छत्तीसगढ़ के राजेश त्रिपाठी, हरिहर पटेल व सबीता रथ, गुजरात के अशोक श्रीमाली, ओड़िसा के प्रफुल्ल प्रधान, बिहार के संतोष व झारखंड से कुमार चंद्र मार्ड, मुन्नी हांसदा आदि भाग ले रहे हैं.